गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 178
दि. 30.10.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों का 'कैश फॉर जॉब' घोटाला उजागर

2,500 से अधिक पदों पर 25 से 35 लाख रुपये तक में हुई भर्ती

(जीएनएस)। चेन्नई। तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों के नाम पर हुआ एक बड़ा 'कैश फॉर जॉब' घोटाला राज्य की राजनीति में भूचाल ला गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने खुलासा किया है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉटर सप्लाई (MAWS) विभाग में 2,538 पदों पर भर्ती के दौरान भारी पैमाने पर रिश्वतखोरी और हेराफेरी की गई। हर पद के लिए 25 से 35 लाख रुपये तक की अवैध वसूली की गई थी। ईडी ने इस पूरे घोटाले का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर तमिलनाडु पुलिस को 232 पन्नों का डोजियर सौंपा है। इसमें न केवल आरोपी अधिकारियों और बिचौलियों के नाम शामिल हैं, बल्कि उन उम्मीदवारों की सूची भी दी गई है जिन्होंने पैसे देकर चयन हासिल किया। ईडी ने कहा है कि यह मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि "संस्थागत धोखाधड़ी" का है, जिसमें सत्ता के उच्च पदों पर बैठे लोग भी शामिल हो सकते हैं।

रिश्वत का खेल और फर्जी चयन की परतें

ईडी की रिपोर्ट के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया 2024 में आयोजित की गई थी। इस दौरान परीक्षा के परिणामों में हेराफेरी कर कुछ उम्मीदवारों को "पैसे के बल पर" पास घोषित किया गया। आरोप है कि लगभग 150 उम्मीदवारों को अगस्त 2025 में फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र जारी किए गए। एजेंसी का कहना है कि ये नियुक्तियां बिचौलियों और दलालों के माध्यम से की गईं, जो उम्मीदवारों से करोड़ों रुपये की रकम इकट्ठा कर विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाते थे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि कई अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में उस समय जोड़े गए जब इंटरव्यू प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसका मतलब है कि भर्ती परिणामों में बाद में फेरबदल किया गया ताकि "भुगतान करने वाले" उम्मीदवारों को जगह दी जा सके।

अन्ना यूनिवर्सिटी की भूमिका पर संदेह

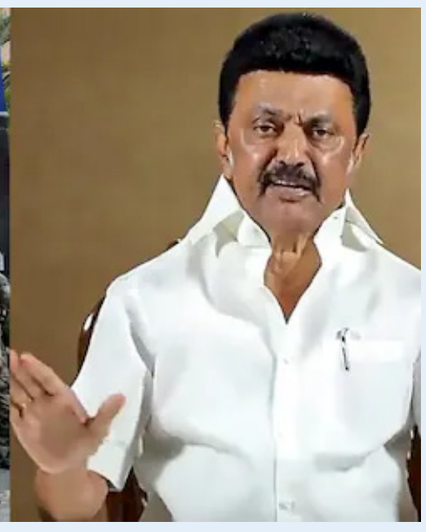

ईडी ने अपनी रिपोर्ट में अन्ना यूनिवर्सिटी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, क्योंकि भर्ती परीक्षा की जिम्मेदारी इसी विश्वविद्यालय को सौंपी गई थी। एजेंसी का दावा है कि परीक्षा केंद्रों के चयन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परिणामों की निगरानी में कई स्तरों पर अनियमितताएं की गईं। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को "डिजिटल रूप से संशोधित" किया गया ताकि पहले से तय उम्मीदवारों के अंक बढ़ाए जा सकें।

ईडी का मानना है कि इस पूरे घोटाले की शुरुआत विश्वविद्यालय के भीतर से हुई और बाद में यह नेटवर्क विभागीय अधिकारियों तक फैला।

विभाग की सफाई और राजनीतिक तूफान

MAWS विभाग के सचिव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी नियुक्तियां "पारदर्शी और नियमों के अनुसार" की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ईडी से किसी आधिकारिक पत्र की जानकारी नहीं मिली है।

हालांकि, जैसे ही यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, राज्य की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि "तमिलनाडु में नौकरी अब योग्यता से नहीं, रिश्वत से मिलती है। डीएमके सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है और यह घोटाला इसका प्रमाण है।"

उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "यह सिर्फ एक विभाग का मामला नहीं, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रतीक है। जिन नौजवानों ने मेहनत से परीक्षा पास की, उनका भविष्य लूट लिया गया।"

ईडी की आगे की कार्रवाई

ईडी ने अपनी रिपोर्ट में तमिलनाडु पुलिस से मांग की है कि वह इस घोटाले में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करे और संबंधित बैंक खातों, संपत्तियों और डिजिटल रिकॉर्ड को जब्त करे। एजेंसी का मानना है कि इस नेटवर्क के तार दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद तक फैले हुए हैं, जहां से पैसों का प्रवाह नियंत्रित किया जा रहा था।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक पदाधिकारी भी पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं।

युवाओं में आक्रोश और भरोसे का संकट

इस घोटाले ने राज्य के युवाओं में भारी रोष पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर "#CashForJobScam" ट्रेंड कर रहा है और लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की बचत खर्च कर परीक्षाओं की तैयारी की थी, लेकिन अब उनका विश्वास तंत्र से उठ गया है।

एक अभ्यर्थी ने कहा, "हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, फिर भी नौकरी उन लोगों को मिलती है जो पैसे देते हैं। अब न्याय की उम्मीद सिर्फ अदालत और जनता से है।"

तमिलनाडु में यह घोटाला राज्य की नौकरशाही और राजनीतिक नैतिकता दोनों पर गहरा सवाल खड़ा कर रहा है। ईडी की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि संस्थागत शुद्धिकरण की जरूरत है।

एनआरसी के डर से आत्महत्या के बाद बंगाल में सियासी घमासान, टीएमसी ने अमित शाह पर एफआईआर की मांग की, भाजपा बोली- राजनीतिक नाटक

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की आत्महत्या ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी क्षेत्र में 45 वर्षीय प्रदीप कर ने कथित रूप से एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) और मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर फैलती अफवाहों के बीच आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

बुधवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी खुद मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह मौत भाजपा द्वारा एनआरसी और एसआईआर के नाम पर लोगों में डर फैलाने का नतीजा है। अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि "एनआरसी और सीएए के नाम पर भाजपा बंगाल में सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की कोशिश कर रही है। प्रदीप कर जैसे लोग इसी भय के शिकार हो रहे हैं।" टीएमसी का कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता सूची के "स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन" (SIR) की प्रक्रिया को लेकर जनता में भ्रम फैलाया गया है कि यह एनआरसी की शुरुआत है। इस डर से प्रदीप कर ने आत्महत्या कर ली। पार्टी ने इसे भाजपा और चुनाव आयोग की "संयुक्त साजिश" करार दिया। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रदीप कर की आत्महत्या का एनआरसी या एसआईआर से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि "प्रदीप कर का नाम 2002 की मतदाता सूची में था और उन्होंने उसी वर्ष विधानसभा चुनाव में मतदान भी किया था। टीएमसी अब हर घटना को एनआरसी से जोड़कर जनता को गुमराह कर रही है।" अधिकारी ने यह भी कहा कि "राज्य में प्रशासनिक विफलता को छिपाने के लिए तृणमूल भावनात्मक राजनीति का सहारा ले रही है।" इस बीच, घटना के बाद स्थानीय इलाकों में तनाव फैल गया है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदीप कर के परिजनों ने बताया कि वे बीते कुछ दिनों से बेहद तनाव में थे और लगातार इस बात की चिंता कर रहे थे कि अगर एनआरसी लागू हुआ तो उनका नाम नागरिकों की सूची में नहीं आएगा। उधर, कूचबिहार जिले में भी ऐसी ही एक घटना ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। दिनहाटा के जीतपुर निवासी 63 वर्षीय खैरुल शेख ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर चिंतित होकर जहर खा लिया।

तेलंगाना कैबिनेट में पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन की एंट्री से सियासी समीकरणों में हलचल, 31 अक्टूबर को लेंगे मंत्री पद की शपथ

(जीएनएस)। हैदराबाद। क्रिकेट के मैदान से लेकर राजनीति के गलियारों तक अपनी पहचान बनाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान और वर्तमान एमएलसी मोहम्मद अजहरुद्दीन अब तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। वे 31 अक्टूबर को राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी रणनीतिक है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से ही मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व न मिलने की आलोचना हो रही थी।

अजहरुद्दीन के शामिल होने से रेवंत रेड्डी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा जुड़ जाएगा। फिलहाल राज्य की कांग्रेस सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। अजहरुद्दीन

इस सरकार में पहले मुस्लिम मंत्री होंगे। उनके शपथ ग्रहण के साथ कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 16 हो जाएगी, जबकि संवैधानिक सीमा 18 की है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह फैसला आगामी उपचुनावों को देखते हुए बेहद सोच-समझकर लिया गया है। जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है, जहां मुस्लिम मतदाता लगभग 30 प्रतिशत हैं। यह वही सीट है, जहां से अजहरुद्दीन ने 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें बीआरएस के मगंती गोपीनाथ ने 16,337 वोटों से हराया था। अब उसी क्षेत्र में उपचुनाव के ऐन पहले अजहरुद्दीन को मंत्री बनाए जाने से कांग्रेस का इरादा मुस्लिम वोट बैंक को साधने का साफ नजर आ रहा है।

जुबली हिल्स सीट पर करीब 3.90 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1.20 से 1.40 लाख मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं। ऐसे में अजहरुद्दीन की सियासी हैसियत और उनका धार्मिक प्रतिनिधित्व कांग्रेस को इस उपचुनाव में सीधा लाभ दिला सकता है। इस उपचुनाव में बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ, कांग्रेस के वल्लाला नवीन यादव और बीजेपी के लंकला दीपक रेड्डी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों प्रमुख दलों ने इस बार कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है।

कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अजहरुद्दीन का मंत्री बनना न केवल जुबली हिल्स बल्कि पूरे हैदराबाद और दक्षिण तेलंगाना के मुस्लिम मतदाताओं में सकारात्मक संदेश देगा। उनके क्रिकेट करियर की लोकप्रियता और स्वच्छ छवि पार्टी के लिए एक नया आकर्षण पैदा कर सकती है।

दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर "धार्मिक तुष्टिकरण" का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस केवल चुनावी लाभ के लिए धर्म आधारित राजनीति कर रही है, जबकि बीआरएस ने इस फैसले को "राजनीतिक स्टंट" बताया है।

फिलहाल रेवंत रेड्डी सरकार को उम्मीद है कि अजहरुद्दीन का प्रवेश न केवल उसकी राजनीतिक छवि को सशक्त करेगा, बल्कि राज्य की खेल और युवा नीतियों में भी नई ऊर्जा भरेगा। क्रिकेट के मैदान पर अपनी शानदार कप्तानी के लिए मशहूर रहे अजहरुद्दीन अब राजनीति के पिच पर कांग्रेस के लिए रन बनाने को तैयार हैं।

कर्नाटक में 'नवंबर क्रांति' की चर्चा तेज, डीके शिवकुमार ने कांग्रेस नेताओं को दी नसीहत—"तनाव न लें, पार्टी आलाकमान पर भरोसा रखें"

(जीएनएस)। बंगलूरू। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के साढ़े दो साल पूरे होने वाले हैं और इसी के साथ एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की चर्चा सियासी गलियारों में गर्म हो गई है। बीते कुछ महीनों से यह अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को नवंबर के महीने में सत्ता की कमान सौंपी जा सकती है। इन अटकलों को लेकर पार्टी के भीतर भी हलचल तेज है, हालांकि कोई भी नेता खुलकर कुछ कहने से बच रहा है। इस बीच बुधवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस नेताओं को 'नवंबर क्रांति' की चर्चा से दूर रहने की सलाह दी। बंगलूरू में एक कार्यक्रम के दौरान शिवकुमार ने कहा, "मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री पद में बदलाव की बातें सिर्फ राजनीतिक अफवाहें हैं। पार्टी आलाकमान जो भी निर्णय लेगा, हम सब उसके साथ हैं। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जनता के विश्वास को बनाए रखना चाहिए।" शिवकुमार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कुछ दिन पहले यह संकेत दिया था कि अगर कांग्रेस हाईकमान चाहेंगे, तो वे पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। सिद्धारमैया के इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं पर परोक्ष जवाब मान रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता साझा करने का एक 'जेंटलमैन एग्रीमेंट' किया था, जिसके तहत 2.5 साल बाद नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बनी हुई थी। यही वजह है कि नवंबर का महीना आते ही राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पार्टी इस वक्त किसी भी प्रकार के राजनीतिक अस्थिरता के जोखिम में नहीं जाना चाहेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पहले ही विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लगातार हमलों और केंद्र से फंड रोकने के आरोपों का सामना कर रही है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन से पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है। राज्य कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "डीके शिवकुमार पार्टी के मजबूत संगठनकर्ता हैं, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरी तरह लागू करना है। सिद्धारमैया के नेतृत्व में कई योजनाएं जैसे 'गृहलक्ष्मी', 'शक्ति' और 'अन्न भाग्य' ने लोगों के बीच लोकप्रियता पाई है। ऐसे में फिलहाल बदलाव की संभावना बहुत कम दिखती है।" वहीं भाजपा ने इस राजनीतिक हलचल पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जनता के विकास कार्यों को प्रभावित कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, "कांग्रेस सरकार अब दो भागों में बंटी हुई है—एक सिद्धारमैया गुट और दूसरा डीके शिवकुमार गुट।

पूर्व मंत्री जेनिथ संगमा की घर वापसी से मेघालय की सियासत में नई हलचल, कांग्रेस में फिर शामिल होकर बोले—"अब असली संघर्ष कांग्रेस के साथ"

(जीएनएस)। शिलांग। मेघालय की राजनीति में बुधवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब राज्य के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता जेनिथ संगमा ने औपचारिक रूप से एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से इस्तीफा देने के महज एक दिन बाद उनकी कांग्रेस में वापसी को लेकर पार्टी ने शिलांग में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने एआईसीसी सचिव और मेघालय प्रभारी ए. चेल्लाकुमार को पत्र लिखकर जानकारी दी कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेनिथ संगमा की पुनः सदस्यता को मंजूरी दे दी है। इसके बाद मेघालय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विंसेंट एच. पाला, विधायक रॉनी लिंडोह, डेबराह मारक सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संगमा का स्वागत किया गया। कांग्रेस में लौटने के बाद जेनिथ संगमा ने कहा, "मेरे लिए कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। मैंने देखा कि प्रदेश में लोगों की उम्मीदें अब भी कांग्रेस से जुड़ी हैं। मैं अपने क्षेत्र और राज्य के विकास के लिए एक बार फिर कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। यह वापसी किसी पद या महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि जनहित के संघर्ष के लिए है।" संगमा ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की राजनीति दिशा से भटक गई है और अब समय आ गया है कि कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच विश्वास बहाली के लिए मजबूत संगठन के रूप में उभरे। उन्होंने कहा, "राज्य के लोग भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अव्यवस्था से परेशान हैं। ऐसे में हमें एकजुट होकर जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।" बता दें कि जेनिथ संगमा 2021 में अपने बड़े भाई और मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के साथ कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हुए थे।

डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर नया शिकंजा, सीबीआई ने दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का मामला — रिश्वतखोरी से लेकर करोड़ों की संपत्ति तक खुला काला खेल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर भ्रष्टाचार का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले रिश्वतखोरी के मामले में रंगे हाथ पकड़े जाने और अब सीबीआई द्वारा उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का नया मामला दर्ज किए जाने के बाद यह मामला राज्य की पुलिस सेवा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सीबीआई ने बुधवार को भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(b) के तहत केस दर्ज किया। जांच एजेंसी के अनुसार, भुल्लर के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति होने के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। उनके पास से अब तक 7.5 करोड़ रुपए नकद, 2.5 किलो सोना, 26 महंगी घड़ियां, दो लग्जरी कारें, 100 लीटर शराब और करीब 50 संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। भुल्लर को 16 अक्टूबर को सीबीआई ने मोहाली स्थित उनके कार्यालय से उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ के एक कबाड़ व्यापारी से पांच

लाख रुपये रिश्वत के रूप में ले रहे थे। व्यापारी ने आरोप लगाया था कि डीआईजी लगातार उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह हर महीने "सेवा-पानी" के नाम पर उन्हें पैसे दे, ताकि पुलिस की कार्रवाई से बचा जा सके। व्यापारी की शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर भुल्लर को रंगे हाथ पकड़ लिया था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने उनके आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में नकदी, सोना और संपत्तियों के दस्तावेज मिले। अब एजेंसी उनकी संपत्तियों की वैधता की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह संपत्ति कब, कैसे और किन स्रोतों से अर्जित की गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, भुल्लर की आय के मुकाबले उनके पास मिली संपत्ति कई गुना अधिक है, जो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार और अवैध कमाई की ओर इशारा करती है। जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ नया मामला दर्ज कर लिया है और संपत्तियों से जुड़े बैंक खातों, बेनामी लेन-देन और विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्होंने विभिन्न जिलों में एसएसपी और डीआईजी के रूप में सेवा दी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन पर भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के आरोप लगते रहे हैं। उनके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें पुलिस विभाग में लंबित थीं, जिनकी जांच अधूरी रह गई थी। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद पंजाब पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कई अधिकारी अब अपने लेन-देन और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में जुट गए हैं, क्योंकि यह मामला राज्य की पुलिस प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर कर रहा है।

बेंगलुरु के मंदिर में बांग्लादेशी नागरिक की गुंडागर्दी से मचा हड़कंप, श्रद्धालुओं ने दबोचा आरोपी

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बुधवार को उस समय तनाव की चपेट में आ गया जब मराठाहल्ली के पास देवरबिसनहल्ली स्थित श्री वेणुगोपाल मंदिर में एक व्यक्ति ने अचानक घुसकर उत्पात मचा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने नशे की हालत में मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मूर्तियों पर जूते से वार करने की कोशिश की और "अल्लाह हू अकबर" चिल्लाते हुए श्रद्धालुओं को भड़काने की कोशिश की। हालांकि, मंदिर कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की तत्परता से उसे तुरंत पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 45 वर्षीय कबीर मंडल के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर बांग्लादेश का नागरिक है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। श्रद्धालु भक्ति स्थल पर इस तरह की हरकत से बेहद आक्रोशित दिखे। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी सीधे गर्भगृह की ओर बढ़ रहा था और प्रवेश द्वार पर रखी मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान लोगों ने उसे घेरकर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इसमें आरोपी को मंदिर के भीतर हंगामा करते और फिर भीड़ द्वारा पकड़े जाने के दृश्य साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे में धुत था और प्रारंभिक पूछताछ में उसने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वह पिछले चार से पांच सालों से इसी इलाके में मोची का काम कर रहा था और खुद को मजदूर बताता था। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि वह भारत में अवैध रूप से कैसे घुसा और उसके पीछे कोई संगठनात्मक या सांप्रदायिक उद्देश्य तो नहीं था। स्थानीय पुलिस ने उसके खिलाफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं हिंदू संगठनों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह नशे में की गई हरकत लगती है, लेकिन आरोपी की नागरिकता और उसकी गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है। बेंगलुरु जैसे संवेदनशील शहर में मंदिर परिसर में इस तरह की घटना ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर स्थानीय लोग तत्परता नहीं दिखाते तो मंदिर की पवित्र मूर्तियों को भारी नुकसान हो सकता था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी से केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ कर सकती हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं था।

पश्चिम रेलवे द्वारा वेरावल ⇌ गांधीग्राम के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाएगी

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तिथियाँ	प्रस्थान	आगमन
09226	वेरावल - गांधीग्राम	31.10.2025 से 10.11.2025 तक	21:20 बजे (दैनिक)	8:00 बजे (दुसरे दिन)
09225	गांधीग्राम - वेरावल	01.11.2025 से 11.11.2025 तक	22:00 बजे (दैनिक)	8:45 बजे (दुसरे दिन)

होल्ट: मालिया हटिना, केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, वीरपुर, गोंडल, भक्तिनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, वाधवान सिटी, बोटाद, धंधुका, ढोलका, बावला और सरखेज स्टेशन दोनों दिशाओं में।

संरचना: एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे।

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन संख्या 09226 और 09225 की बुकिंग 30.10.2025 से सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर चलायी जाएगी ।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly
हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly
हमें फॉलो करें: Instagram/WesternRly

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ लाएँ।

संपादकीय

कसौटी पर एसआईआर

उम्मीद के अनुरूप चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण की विधिवत शुरुआत कर दी है। इस चरण में देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीब 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये केवल तीन माह का समय दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में एसआईआर पर लंबे समय से चले विवादों के मद्देनजर, इस प्रक्रिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर उन राज्यों में जहां विपक्षी दल शासित सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु व महाराष्ट्र से ऐसी प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी लोकतंत्र में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिये जरूरी है कि पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। वहीं अयोग्य मतदाता को हटाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर कोई विवाद नहीं माना जा सकता। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया के मद्देनजर पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही तत्काल सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस बाबत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि आगामी एसआईआर का लक्ष्य मतदाता सूचियों की लंबे समय से लंबित राष्ट्रव्यापी सफाई करना है। ऐसे व्यापक संशोधन देश में समय-समय पर हुए हैं और पिछला संशोधन दो दशक पहले हुआ था। जाहिर बात है कि इस लंबे अंतराल के दौरान मतदाता सूचियों में कई विसंगतियां और त्रुटियां उत्पन्न हो गई होंगी। आयोग ने उदाहरण देते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं। देश में निष्पक्ष चुनाव के लिये इन सूचियों का प्रमाणीकरण अपेक्षित है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष दलों की आशंकाओं की अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए। साथ ही लोगों में लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया के प्रति उत्साह बना रहना भी जरूरी है।

दरअसल, कांग्रेस, माकपा, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों को आशंका है कि एसआईआर का इस्तेमाल अवैध मतदाताओं की पहचान की आड़ में लक्षित वास्तविक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिये हो सकता है। वैसे बिहार में हुई कवायद के बाद ज्ञात नहीं है कि यह प्रक्रिया कितने अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने में सफल रही है। निस्संदेह, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा उचित प्रक्रिया-परिश्रम और जनता के विश्वास पर ही टिकी है। निर्विवाद रूप से देश में चुनाव कराने वाली शीर्ष संवैधानिक संस्था की ईमानदारी और निष्पक्षता दोषमुक्त होनी ही चाहिए। चुनाव आयोग को व्यापक सत्यापन, इस प्रक्रिया से जुड़े तमाम हितधारकों के साथ विमर्श और वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार को अक्षुण्ण बनाने हेतु एक ठोस निवारण तंत्र विकसित करने की जरूरत है। विपक्षी दलों द्वारा वोट चोरी और अन्य अनियमितताओं के कथित आरोपों का खंडन ठोस सबूतों के साथ किया जाना चाहिए। ताकि जनता में इस प्रक्रिया को लेकर भरोसा कायम रह सके। वैसे एसआईआर के दूसरे चरण का सकारात्मक पक्ष यह जरूर है कि आयोग ने प्रक्रिया के लिये पर्याप्त समय दिया है ताकि बिहार जैसी जल्दबाजी और अफरातफरी के आक्षेपों से बचा जा सके। निश्चित रूप से आधार कार्ड को सहायक दस्तावेज के रूप में मान्यता देने का लाभ प्रक्रिया के सरलीकरण में मिलेगा। विश्वास किया जाना चाहिए कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सामने आई चुनौतियां इस दूसरे चरण की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का कार्य करेंगी। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दूसरे चरण में शामिल राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों को वैसी परेशानी का सामना न करना पड़े, जैसी कि बिहार के लोगों में सामने आई थी। लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि योग्य मतदाता न छूटे और कोई फर्जी मतदाता लिस्ट में शामिल न होने पाए। यहां उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों में दूसरे चरण के दौरान मतदाता सूचियों को गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से गुजरना है, उनमें से कुछ में अगले साल चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी शामिल हैं। बहरहाल, कोशिश हो कि न ही जनता को परेशानी उठानी पड़े और न ही चुनाव कर्मियों में भ्रम जैसी स्थिति बनी रहे।

इस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त सृजनात्मक विनाश के सिद्धांत की जड़ें हिंदू सनातन संस्कृति में हैं

> मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से मिले इस मानव जीवन को संवारने की दृष्टि से विद्वान संत महात्मा उपदेश देते हैं कि काम एवं अर्थ से सम्बंधित की जाने वाली गतिविधियों को धर्म आधारित होना चाहिए ताकि अंत में मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हो सके।

हिंदू सनातन संस्कृति से सम्बंधित वेदों, पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि मानव जीवन की प्राप्ति, 84 लाख योनियों के चक्र के पश्चात प्राप्त होती है। साथ ही, यह भी माना जाता है कि मानव जीवन की प्राप्ति पिछले जन्मों में किए गए कर्मों को भोगने, भविष्य का निर्माण करने एवं 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करने के लक्ष्य को हासिल करने के अवसर के रूप में मिलती है। अब, यह इस मानव जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी अथवा 84 लाख योनियों के चक्र में एक बार पुनः फंसे रहेंगे। यदि हम अपने कर्मों को लगातार धर्मानुसार करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। इसी आधार पर ही यह कहा भी जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ही देवता भी मानव जीवन को प्राप्त करने की कामना करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से मिले इस मानव जीवन को संवारने की दृष्टि से विद्वान संत महात्मा उपदेश देते हैं कि काम एवं अर्थ से सम्बंधित की जाने वाली गतिविधियों को धर्म आधारित होना चाहिए ताकि अंत में मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हो सके। अतः काम एवं अर्थ को धर्म एवं मोक्ष के बीच स्थान दिया गया है। धर्म का आशय यहां प्रभु परमात्मा की भक्ति अथवा पंथ (रिलीजन) से कतई नहीं हैं बल्कि धर्म से आशय यह है कि किसी भी प्रकार के कार्य को सम्पन्न करने में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किए जाने वाले कार्य से किसी भी जीव जंतु अथवा मानव की हानि नहीं हो इसके ठीक विपरीत हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों से समाजजनों की भलाई हो। अर्थात, निर्धारित नियमों का अनुपलान करते हुए व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों को सम्पन्न

करना ही हमारा धर्म है और यदि हम लगातार धर्म के अनुसार कार्य करते रहेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हो सकेगी। इस प्रकार, हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। किसी भी प्राणी का अहित करना तो दूर, बल्कि इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जाता है। समस्त जीवों में प्रभु परमात्मा का वास माना जाता है और सभी जीवों में एक ही आत्मा का निवास मानकर आपस में एकाकार माना जाता है। "वसुधैव कुटुम्बकम", "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" "सर्वे भवंतु सुखिनः" की भावना का जन्म भी उक्त सिद्धांत के आधार पर ही हुआ है। प्रभु परमात्मा द्वारा निर्धारित की गई उम्र को प्राप्त करने के पश्चात इस जीव को अपना मानुष चोला त्यागकर, इस जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर नयी योनि में जन्म लेना होता है और इसे ही सृजनात्मक विनाश की संज्ञा दी जा सकती है।

हाल ही में, वर्ष 2025 के लिए अर्थशास्त्र विषय में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार जोएल मोक्यर, फिलिप एगियन और पीटर हाविट को "सृजनात्मक विनाश (क्रीएटिव डेस्ट्रक्शन)" एवं "नवाचार संचालित आर्थिक संवृद्धि की व्याख्या" विषय पर शोद्ध करने के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है।

फिलिप एगियन और पीटर हाविट ने सृजनात्मक विनाश के माध्यम से सतत संवृद्धि के सिद्धांत साझा किए हैं। आपने सृजनात्मक विनाश की व्याख्या करने के लिए एक गणितीय मॉडल तैयार किया है। सृजनात्मक विनाश के अनुसार, जब बाजार में नए और बेहतर उत्पाद आते हैं, तो पुराने उत्पाद बेचने वाली कम्पनियां अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो देती हैं या बाजार से बाहर हो जाती है। इसे सृजनात्मक कहा जाता है, क्योंकि यह नवाचार पर आधरित है। यद्यपि यह विनाशकारी भी हैं, क्योंकि पुराने उत्पाद अप्रचलित हो जाते हैं और अपना वाणिज्यिक मूल्य खो देते हैं। इस प्रकार बाजार में नई इकाईयों का पदार्पण होता है एवं पुरानी इकाईयों का विनाश हो जाता है। इसे ही सृजनात्मक विनाश की संज्ञा दी गई है।

ऐसा आभास हो रहा है कि उक्त सिद्धांत की जड़ें हिंदू सनातन संस्कृति से ही निकलती हैं। जिस किसी जीव ने इस धरा पर जन्म लिया है उसे एक दिन तो अपने जीवन का परित्याग करना ही है। मानव जीवन की प्राप्ति भी कुछ उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए होती है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात इस मानव जीवन को छोड़ना ही होता है। उसी प्रकार, सृजनात्मक विनाश के सिद्धांत में भी एक समय सीमा के पश्चात उत्पादों के विनिर्माण हेतु बाजार में जब नयी पीढ़ी की इकाईयों का पदार्पण होता है तो पुरानी पीढ़ी की विनिर्माण इकाईयों को बाजार से बाहर हो जाना होता है।

हिंदू सनातन संस्कृति का अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि स्व-सृजक प्रक्रिया एवं रचनात्मक विनाश का सिद्धांत तो भारतीय संस्कृति में पूर्व से ही अंतर्निहित है। भगवान शिव जब तांडव नृत्य करते हैं तो बुरे विचारों का नाश होकर नए विचार जन्म लेते हैं जो प्रकृति का सृजन कर प्रकृति को नई ऊंचाई पर ले जाने में सहायक होते हैं। भगवान शिव भी तांडव नृत्य इस सिद्धांत के आधार पर करते हैं ताकि पृथ्वी पर आवश्यक विनाश हो सके एवं नयी प्रकृति का पुनर्निर्माण हो सके। "शिव तांडव के सृजनात्मक विनाश सम्बंधी सिद्धांत" को ही अर्थशास्त्र में लागू करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक उत्पादन इकाई की अपनी एक उम्र तय होती है और इस खंडकाल में सामान्यतः नवाचार होने के चलते पुरानी इकाईयां बंद हो जाती हैं और यहां यह कहा गया है कि इन पुरानी इकाईयों को नष्ट होने देना चाहिए ताकि नवाचार के साथ नई उत्पादन इकाईयों को स्थापित कराया जा सके। यह सिद्धांत शिव तांडव की तरह विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चलता रहता है।

जोएल मोक्यर ने तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों की पहचान की है और उन्होंने उन तंत्रों का वर्णन किया है जो वैज्ञानिक सफलताओं और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को एक दूसरे को बढ़ाने तथा एक स्व-सृजक प्रक्रिया बनाने में सक्षम बनाते हैं। उन्होंने सतत संवृद्धि के लिए आवश्यक कारकों की पहचान की हैं। इनमें शामिल हैं - उपयोगी ज्ञान का सतत प्रवाह - जिसमें (1) प्रस्तावात्मक ज्ञान (प्रोपोजीशनल नोलेज), जो दर्शाता है कि कोई व्यक्ति काम क्यों करता है, (2) निर्देशात्मक ज्ञान (प्रेसक्रिप्टिव नोलेज) जो वर्णित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा काम करने के लिए क्या आवश्यक है, शामिल है। इसी प्रकार वाणिज्यिक ज्ञान द्वारा विचारों को वाणिज्यिक उत्पादों में बदला जाता है और इस परिवर्तन के प्रति सामाजिक खुलापन होना चाहिए जो पुराने उत्पादों के स्थान पर नए उत्पादों को स्वीकार करने की इच्छा रखते हों।

इसी प्रकार स्व-सृजक प्रक्रिया के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि हिंदू सनातन संस्कृति में मनुष्य का इस धरा पर जन्म 84 लाख योनियों से अपने आप को मुक्त करने के उद्देश्य से होता है अतः उसे ज्ञान रहता है कि उसे किस प्रकार के कर्म इस मानुष जीवन में करना हैं और क्यों करना है। इन निर्धारित कर्मों को करते हुए मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करने हेतु सदैव ही प्रयासरत रहता है। इस ही स्व-सृजक प्रक्रिया कहा जा सकता है।

प्रेरणा

आत्मज्ञान का रत्न: जब बुद्ध ने बताया चौदहवां धन, जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है

एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गंगा तट के समीप जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। लंबे समय तक चलते रहने से सभी थक चुके थे। दोपहर की तपती धूप सिर पर थी, और धरती से उठती गरम हवा उनके कदमों को और भारी बना रही थी। बुद्ध ने अपने शांत स्वर में कहा, "चलो, इस वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करें।" सब शिष्य वहीं रुक गए, किसी ने जल पिया, कोई ध्यानमग्न हो गया, और कोई बुद्ध के चरणों के समीप बैठकर मौन साधना करने लगा। वातावरण में एक गहरी शांति थी — बस पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज़ें।

थोड़ी देर बाद बादल घिर आए, हवा ठंडी हुई और आसमान अंधेरा हो गया। कुछ शिष्यों के मन में अजीब-सी बेचैनी होने लगी। तभी एक जिज्ञासु शिष्य ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए प्रश्न किया, "भगवान, आपने कहा है कि चंद्रमा की चौदह कलाएं होती हैं, जो उसे पूर्ण बनाती हैं। क्या मनुष्य के भीतर भी कोई ऐसी चौदह कलाएं या रत्न होते हैं, जो उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं?"

बुद्ध ने अपनी आँखें बंद कीं, कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, "मनुष्य के पास चौदह रत्न होते हैं, लेकिन उनमें से तेरह तो उसे प्रकृति अपने उपहार स्वरूप दे देती है। पाँच कर्मेंद्रियां — हाथ, पैर, जिह्वा, गुदा और जननेंद्रिय; पाँच ज्ञानेंद्रियां — आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ; और तीन सूक्ष्म तत्व — मन, बुद्धि और अहंकार। ये तेरह रत्न वह है जिनसे तुम दुनिया को अनुभव करते हो, सोचते हो, और प्रतिक्रिया देते हो। ये प्रकृति की देन हैं।"

शिष्य ने फिर पूछा, "तो फिर चौदहवां रत्न कौन-सा है, भगवान?"

बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, "वह है — चित्त। यह वह रत्न है, जिसे कोई तुम्हें दे नहीं सकता, तुम्हें इसे स्वयं खोजना होता है। जब चित्त निर्मल हो जाता है, तब मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। जब मन में ज्ञान का दीपक जलता है, तभी अंधकार मिटता है और चित्त सच्चे रूप में प्रकट होता है। वही चौदहवां रत्न है — जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "देखो, शरीर का सौंदर्य, धन, शक्ति — ये सब क्षणिक हैं। वे तेरह रत्न तो तुम्हारे पास हैं, लेकिन जब तक चौदहवां रत्न, यानी चित्त, जागृत नहीं होता, तब तक तुम अधूरे हो। जैसे बिना दीपक के मंदिर अंधकार में डूबा रहता है, वैसे ही बिना चित्त के प्रकाश के मनुष्य जीवन मोह और अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है।"

वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। बुद्ध की वाणी से जैसे सृष्टि का रहस्य खुल गया हो। हवा ठहर गई, वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गईं, और शिष्यों के हृदय में एक ही भाव रह गया — कि सच्चा धन न शरीर में है, न संसार में, बल्कि उस निर्मल चित्त में है जो आत्मा को उसके सत्य स्वरूप से मिलाता है।

बुद्ध ने अंत में कहा, "मनुष्य के जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह अपने भीतर उस चौदहवें रत्न को खोज ले। जो इस रत्न को पा लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बाहर मत ढूंढो, क्योंकि ज्ञान बाहर नहीं — तुम्हारे ही भीतर है। जब भीतर दीपक जलेगा, तो सारा अंधकार स्वयं मिट जाएगा।"

उस दिन बुद्ध के इन शब्दों ने शिष्यों के मन में आत्मबोध का दीप जला दिया। उन्होंने जाना कि आत्मज्ञान का रत्न कोई वस्तु नहीं, बल्कि अपने चित्त का जागरण है — वही चौदहवां रत्न, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं, बल्कि ज्ञानी बना देता है।

भारत–कनाडा संबंध: सुधार की दिशा में नई पहल और संभावनाएँ

भारत और कनाडा के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुसांस्कृतिक समाज और वैश्विक सहयोग की समान विचारधारा साझा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह संबंध राजनीतिक मतभेदों और कुछ विवादास्पद घटनाओं के कारण तनावपूर्ण दौर से गुज़रा। इसका सबसे अधिक प्रभाव उन आम भारतीय नागरिकों, छात्रों और पेशेवरों पर पड़ा जो कनाडा में अपनी शिक्षा और रोजगार के माध्यम से जीवन निर्माण कर रहे हैं। अब जब दोनों देशों के बीच संबंध सुधार की दिशा में नई पहल दिखाई दे रही हैं, तो उम्मीद की किरण फिर से जाग उठी है।भारत–कनाडा संबंधों में गिरावट की मुख्य वजह रही कनाडा में सक्रिय राष्ट्र विरोध का मुद्दा। भारत ने लगातार यह चिंता जताई कि कनाडा की भूमि का उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इस विषय पर कई बार राजनयिक स्तर पर असहमति और बयानबाजी हुई, जिसने द्विपक्षीय संवाद को प्रभावित किया। स्थिति तब और तनावपूर्ण हुई जब कुछ राजनीतिक समूहों ने कनाडा में देश द्रोही समर्थक प्रदर्शन और हिंसक गतिविधियां आयोजित कीं। भारत की नजर में यह न केवल उसकी आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप था, बल्कि द्विपक्षीय विश्वास को भी कमजोर करने वाला कदम। इन घटनाओं के चलते उच्च-स्तरीय वार्ता ठप पड़ गईं, निवेश और व्यापारिक समझौतों की गति धीमी हो गई, और शिक्षा–वीज़ा जैसे विषयों पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ा। हजारों भारतीय छात्र जो कनाडा में पढ़ाई या नौकरी की तलाश में थे, उन्हें वीज़ा प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

अब हालात धीरे-धीरे बदलते दिखाई दे रहे हैं। हाल के महीनों में दोनों देशों की सरकारों ने संवाद बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की हैं। द्विपक्षीय वार्ता के पुनः प्रारंभ होने से यह संकेत मिला है कि भारत और कनाडा अब अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोग की नई राह पर चलना चाहते हैं। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह है कि कनाडा सरकार ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को अधिक गंभीरता से लेना शुरू किया है। आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी और नियंत्रण के संकेत मिले हैं। यह कदम न केवल भारत के हित में है, बल्कि कनाडा के अपने सामाजिक ताने-बाने की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। आतंक किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक होता है — और यदि कनाडा इस दिशा में ठोस कार्रवाई करता है, तो यह संबंधों में भरोसे का नया अध्याय खोलेगा।

भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से परस्पर लाभकारी रहे हैं। कृषि, तकनीकी, शिक्षा, ऊर्जा और खनन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय आईटी कंपनियां और स्टार्टअप कनाडा में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहे हैं, वहीं कनाडाई कंपनियाँ भारत के विशाल बाजार में निवेश बढ़ा रही हैं। 2023–24 के दौरान राजनीतिक तनाव के चलते व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। कई कंपनियों ने निवेश योजनाएं रोक दीं और दोनों देशों के बीच निर्यात–आयात में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अब सुधार की दिशा में उठाए जा रहे कदम इन अड़चनों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। जैसे ही राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी, निवेश का माहौल बेहतर होगा और नए व्यापारिक समझौते संभव होंगे।

कनाडा भारतीय छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्यों में से एक है। वर्तमान में लगभग तीन लाख से अधिक भारतीय छात्र वहाँ अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर वर्क वीजा पर कनाडा में कार्यरत हैं। इन छात्रों और कामगारों ने दोनों देशों के बीच न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक पुल भी बनाया है। हालांकि, संबंधों में तनाव के चलते वीज़ा नीतियों और वर्क परमिट की प्रक्रियाओं में कठिनाई आने लगी थी। इससे छात्रों की पढ़ाई और करियर पर असर पड़ा। यदि अब संबंधों में स्थिरता आती है, तो वीज़ा प्रक्रिया सुचारू होगी, शैक्षणिक अवसर बढ़ेंगे, और पेशेवर सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

भारत और कनाडा के बीच मानव संबंधों की जड़ें गहरी हैं। कनाडा में चौदह लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो कनाडा के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये प्रवासी समुदाय दोनों देशों के बीच सेतु का काम करता है। जब राजनीतिक माहौल शांत होता है, तो इस प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए अवसर भी बढ़ते हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होता है। भारत–कनाडा संबंधों का सुधार केवल एक राजनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों की साझा आकांक्षा है। स्थिर और सहयोगी संबंध शिक्षा, रोजगार और व्यापार के अवसरों को बढ़ाते हैं, जबकि उग्रवाद और अविश्वास केवल नुकसान पहुंचाते हैं। यदि दोनों देश आपसी सम्मान और सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यह साझेदारी वैश्विक स्तर पर भी एक आदर्श उदाहरण बन सकती है। आगामी वर्षों में उम्मीद की जा सकती है कि भारत और कनाडा आतंकवाद के विरुद्ध साझा नीति अपनाएँगे, व्यापारिक समझौतों को नई गति देंगे और शिक्षा व तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे।

भारत–कनाडा संबंधों का सुधार एक सकारात्मक संकेत है, जो केवल राजनीतिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छात्रों, कामगारों, निवेशकों और आम नागरिकों के जीवन में भी स्थिरता, अवसर और विकास लेकर आएगा। यदि कनाडा खालिस्तानी तत्वों पर ठोस कार्रवाई कर, भारत की चिंताओं को दूर करता है, तो यह न केवल राजनीतिक तनाव कम करेगा बल्कि विश्वास, सहयोग और साझेदारी के नए युग की शुरुआत भी करेगा।

अभियान

अंधविश्वास: युग बदल गया, लेकिन विश्वास का अंधकार अब भी शेष है

मनुष्य सभ्यता के विकास की कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही पुरानी उसकी आस्था और भय की भी कहानी है। आदिम युग से लेकर आज के डिजिटल और अंतरिक्ष युग तक मनुष्य ने तकनीक, ज्ञान, विज्ञान और विचार में अनगिनत ऊँचाइयाँ छुईं, किंतु एक चीज़ उसके साथ साए की तरह चली — अंधविश्वास। वह कभी धर्म के आवरण में छिपा, कभी संस्कृति के रूप में पूजित हुआ, कभी परंपरा बनकर घरों में स्थान पाया और अब तो उसने तकनीक और सोशल मीडिया का भी रूप ले लिया है। यह मनुष्य की मानसिक संरचना की वह परत है जो हर युग में, हर समाज में, हर वर्ग में किसी न किसी रूप में जीवित रहती है।

यदि हम पीछे झाँकें तो पाएँगे कि मनुष्य ने प्रकृति को न समझ पाने के कारण कई प्रतीकों में भय और आशा का रूप देखा। बिजली कड़कने पर देवता क्रोधित हुए, सूखा पड़ा तो देवी नाराज़ हुईं, और जब बारिश हुई तो पूजा सफल मानी गई। इसी अंधकार से अंधविश्वास की पहली चिंगारी जली। समय बीतता गया, पर मनुष्य की यह प्रवृत्ति नहीं बदली। जब विज्ञान ने सवालों के उत्तर देने शुरू किए, तब भी अंधविश्वास ने अपने रूप बदल लिए। पहले जिन मंत्रों, ताबीज़ों और टोटकों पर विश्वास था, आज वे मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन वास्तु परामर्श और डिजिटल अंकशास्त्र में परिवर्तित हो गए हैं।

भारत जैसे परंपराओं से समृद्ध देश में अंधविश्वास की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। काली बिल्ली का रास्ता काटना, नींबू-मिर्च लटकाना, मंगलवार को बाल न कटवाना, या घर की दिशा उत्तर-पूर्व में रखना — ये सब इतने सामान्य हैं कि कोई इन्हें अंधविश्वास मानता ही नहीं। ये अब हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना में शामिल हो चुके हैं। आज भी कई शिक्षित लोग अपशकुन के भय से अपनी यात्रा रोक देते हैं या शुभ दिन देखकर नया काम शुरू करते हैं। यह दिखाता है कि शिक्षा ने ज्ञान दिया, पर अंधकार की जड़ें अभी भी मन में कहीं न कहीं विद्यमान हैं।

वास्तुशास्त्र का उदाहरण लीजिए। विज्ञान और इंजीनियरिंग के युग में भी लोग मानते हैं कि यदि घर की रसोई दक्षिण-पूर्व में होगी तो संपन्नता आएगी, और यदि पूजा घर उत्तर-पूर्व में होगा तो सुख-शांति बनी रहेगी। बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को "वास्तु-कंप्लायंट" बताकर अधिक दाम वसूलते हैं। यह विश्वास अब परंपरा से बढ़कर व्यापार बन चुका है। उसी तरह नींबू-मिर्च का प्रयोग अब इतना आम है कि बाजार में 'ऊर्जा-भरे' नींबू-मिर्च तक बिकते हैं। यह दिखाता है कि अंधविश्वास कैसे धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता संस्कृति में भी जगह बना लेता है।

अंधविश्वास का यह सिलसिला केवल पारंपरिक समाजों तक सीमित नहीं है। पश्चिमी दुनिया में भी संख्या 13 को लेकर भय इतना गहरा है कि बड़े-बड़े होटल और भवनों में 13वीं मंज़िल ही नहीं होती। वहीं भारत में लोग 1111 या 9999 जैसे नंबरों को लाखों में खरीदते हैं। यह अंकशास्त्र का नहीं, मानसिक आश्वासन का खेल है — जैसे कोई व्यक्ति यह मानकर जीता है कि किसी वस्तु या अंक में छिपा सौभाग्य उसे जीवन की अनिश्चितताओं से बचा लेगा।

डिजिटल युग ने अंधविश्वास को नए पंख दिए हैं। अब डर और विश्वास की कहानियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से पलभर में करोड़ों लोगों तक पहुँच जाती हैं। "इस संदेश को दस लोगों को भेजो, नहीं तो दुर्भाग्य आएगा" — यह वह आधुनिक टोटका है जो पुराने जमाने की "चिट्ठी आगे बढ़ाओ" परंपरा का नया संस्करण है। कोविड-19 महामारी के समय सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें और विश्वास फैलाए गए — कहीं कहा गया गोमूत्र पीने से कोरोना मिटेगा, कहीं थाली बजाने से वायरस भाग जाएगा। लोग भय में जी रहे थे, और भय हमेशा तर्क पर भारी पड़ता है। इसीलिए संकट के समय अंधविश्वास सबसे अधिक पनपता है।

खेल, राजनीति और मनोरंजन की दुनिया भी इससे अछूती नहीं है। क्रिकेट खिलाड़ी अपने "लकी बैट" या "लकी ग्लव्स" को सफलता का कारण मानते हैं। कोई नेता हर बार एक ही मंदिर से चुनाव प्रचार शुरू करता है, कोई खास रंग का कुर्ता शुभ मानता है। इन सबका मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि मनुष्य अपने भीतर की अनिश्चितता को किसी बाहरी प्रतीक से बाँधना चाहता है — ताकि यदि असफलता मिले, तो दोष खुद पर नहीं, उस अदृश्य शक्ति पर डाला जा सके।

आज तकनीक ने अंधविश्वास को "टेक्नो-सुपरस्टिशन" में बदल दिया है। यूट्यूबर्स मानते हैं कि यदि उनका वीडियो किसी खास संख्या पर लाइक पहुँचे तो एल्गोरिद्म उन्हें ऊपर उठाएगा। निवेशक ग्रहों की स्थिति देखकर क्रिप्टो खरीदते हैं। ऑनलाइन गेमर किसी खास समय पर लॉग-इन करके जीत का विश्वास पालते हैं। यह सब आधुनिकता की सतह पर लिपटा वही पुराना विश्वास है, जिसे कभी देवी-देवता, कभी अंक, और अब एल्गोरिद्म के नाम पर पूजा जा रहा है।

मनोविज्ञान के अनुसार अंधविश्वास का जन्म भय, असुरक्षा और नियंत्रण की इच्छा से होता है। जब मनुष्य किसी घटना को समझ नहीं पाता, तो वह उसे किसी शक्ति से जोड़ देता है। यदि संयोगवश वह घटना उसके पक्ष में जाती है, तो उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है। यही बार-बार दोहराकर वह अंधविश्वास का रूप ले लेता है। मनुष्य का मस्तिष्क सरल व्याख्याओं को पसंद करता है — इसलिए जब विज्ञान जटिल उत्तर देता है, तो मन विश्वास का आसान रास्ता चुन लेता है।

फिर भी, अंधविश्वास को पूरी तरह मिटाना असंभव है। क्योंकि वह केवल सामाजिक नहीं, मानसिक प्रवृत्ति है। जब तक जीवन में अनिश्चितता, भय, और आशा हैं, तब तक कोई न कोई रूप में अंधविश्वास रहेगा। परंतु उसका प्रभाव शिक्षा, वैज्ञानिक चेतना और विवेक से सीमित किया जा सकता है। यदि परंपरा मनुष्य को जोड़ती है, तो तर्क उसे दिशा देता है। आज जब मानवता मंगल ग्रह पर कदम रख चुकी है, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वयं निर्णय ले रही है, तब भी यदि कोई व्यक्ति नींबू-मिर्च, वास्तु, या "लकी नंबर" के भरोसे निर्णय लेता है, तो यह बताता है कि विज्ञान ने भले अंतरिक्ष को जीत लिया हो, पर मनुष्य का मन अभी भी विश्वास और भय की जटिल भूलभुलैया में कैद है। यही वह सत्य है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि असली अंधकार बाहर नहीं, भीतर है — और उसे मिटाने का दीपक केवल तर्क, शिक्षा और आत्मजागरूकता ही जला सकती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से एकता नगर में ₹१२१९ करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण

एकता नगर को और भी अधिक सुविधा संपन्न बनाने वाली परियोजनाओं का लोकार्पण

- भगवान बिरसा मुंडा भवनः आदिवासी जननायक को श्रद्धांजलि स्वरूप निर्मित भव्य भवन (₹ ३०३ करोड़)
- GSEC और SSNNL के कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाएं (₹ ५६ करोड़)
- हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट (फेज-१)ः पर्यटकों के आकर्षण में होगी और वृद्धि (₹ ५४ करोड़)
- सतपुड़ा प्रोटेक्शन वॉल और रिवरफ्रंटः एकता नगर बनेगा और भी सुंदर व आकर्षक (₹ २० करोड़)
- २५ ई-बसों और ई-बस चार्जिंग डिपो के लोकार्पण से केवड़िया के ग्रीन ग्रोथ को मिलेगा नया वेग (₹ ३५ करोड़)
- वामन वृक्ष वाटिका (बोनसाई गार्डन)ः बोनसाई वृक्ष बनेंगे आकर्षण का केंद्र (₹ १८ करोड़)

"विकास भी और विरासत भी" मंत्र के समन्वय के साथ विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यासः

- रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया म्यूज़ियमः देश के राजा-महाराजाओं के इतिहास, संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाला संग्रहालय (₹ ३६७ करोड़)
- वीर बालक उद्यानः वर्तमान पीढ़ी को पौराणिक बालवीरों की गाथाओं से परिचित कराने वाला उद्यान (₹ ९० करोड़)
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सः एकता नगर में पर्यटन के साथ खेल गतिविधियों को भी मिलेगा नया प्रोत्साहन (₹ २३ करोड़)

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय वडाप्रधान

विज़िटर सेंटर

श्रेष्ठ भारत भवन गार्डन

स्मार्ट बस-स्टैंड

श्री भूपेंद्रभाई पटेल
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात

रॉयल किंगडम्स ऑफ़ इंडिया म्यूज़ियम

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

बिरसा मुंडा भवन

दिनांकः ३०.१०.२०२५, गुरुवार | **समयः** दोहपर ०४.०० बजे
स्थानः एकता नगर, जिला नर्मदा

**हर घर स्वदेशी,
घर-घर स्वदेशी**

आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है **"एक भारत, श्रेष्ठ भारत"**।
श्री हर्ष संघवी, माननीय उपमुख्यमंत्री, गुजरात

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के “नागरिक देवो भव” के अभिगम को राज्य में डिजिटल गुड गवर्नेंस के माध्यम से साकार करने की दिशा में GARC की पाँचवीं रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (GARC) की पाँचवीं रिपोर्ट सौंपी गई

- ‘एक राज्य –एक पोर्टल’ के विज़न के साथ “सरकार नागरिकों के द्वार पर” के सिद्धांत को व्यवहार में उतारने हेतु तैयार की गई सिफारिशों पर आधारित रिपोर्ट
- सिंगल साइन-ऑन सिस्टम (SSO) के माध्यम से एक ही यूज़र आईडी से मिलेंगी नागरिकों को सभी सेवाएँ
- राज्य सरकार की सेवाओं के लिए बार-बार जानकारी देने से मिलेगी मुक्ति, “एक बार जानकारी दें, अनेक बार लाभ पाएं” का लक्ष्य होगा साकार
- डिजिटल गुजरात 2.0 पोर्टल के माध्यम से शासन प्रणाली को प्रोसेस-सेन्ट्रिक से सिटिजन-सेन्ट्रिक रूप में परिवर्तित कर अधिक संवेदनशील सेवा वितरण लागू करने की सिफारिश

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के ‘नागरिक देवो भव’ के सिद्धांत को डिजिटल गुड गवर्नेंस के माध्यम से साकार करते हुए, विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में विकसित गुजरात @2047 से एक नया अध्याय रचने का संकल्प व्यक्त किया है।

उल्लेखनीय है कि इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे और कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधारों के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (GARC) का गठन किया है।

अब तक इस आयोग ने राज्य सरकार को चार सिफारिश रिपोर्टें सौंपी हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को GARC द्वारा 12 प्रमुख सिफारिशों के साथ तैयार की गई पाँचवीं रिपोर्ट सौंपी गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी ने डिजिटल तकनीक के व्यापक उपयोग के माध्यम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा विचार देश को दिया है, जिससे नागरिक केंद्रित सेवाएँ सरल, सुगम और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने योग्य बन सकें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी गई GARC की पाँचवीं रिपोर्ट में इस विचार के अनुरूप “वन स्टेट – वन पोर्टल” (एक राज्य – एक पोर्टल) पहल अपनाने की सिफारिश की गई है। गुड गवर्नेंस के मॉडल स्टेट के रूप में प्रसिद्ध गुजरात में हर नागरिक को एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएँ एक क्लिक पर उपलब्ध कराने तथा ‘गवर्नमेंट ऐट द डोरस्टेप ऑफ सिटिजन’ के मंत्र को साकार करने की दिशा में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई है कि सिंगल साइन-ऑन सिस्टम (SSO) के माध्यम से नागरिकों को एक ही यूज़र आईडी से सभी सेवाएँ मिलें। साथ ही, एक बार भरी गई जानकारी को आधार या डिजीलॉकर सेवाओं से जोड़कर विभिन्न सेवाओं में स्वतः उपयोग में लाने की व्यवस्था विकसित की जाए।

इससे नागरिकों को बार-बार वही जानकारी देने से मुक्ति मिलेगी और “एक बार जानकारी दें, अनेक बार लाभ पाएं” का उद्देश्य पूरा होगा।

GARC की इस पाँचवीं रिपोर्ट का

मुख्य फोकस डिजिटल गुजरात 2.0 पोर्टल विकसित करने पर है। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक कार्यप्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी और सरकार व नागरिकों के बीच संवाद और अधिक सुगम बनेगा।

इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि केवल नागरिकों के आवेदन की प्रतीक्षा करने के बजाय उनकी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाकर स्मार्ट अलर्ट सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को उनकी पात्रता के अनुसार सामाजिक कल्याण योजनाओं और लाइफ-साइकल आधारित मार्गदर्शन की जानकारी प्रदान की जाए ताकि एक सक्रिय, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण प्रणाली लागू हो सके।

रिपोर्ट में प्रमुख नागरिक सेवाओं के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल वर्कफ्लो की भी अनुशंसा की गई है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि आवेदन, अनुमोदन और स्थिति अपडेट वास्तविक समय में उपलब्ध हों, जिससे पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़े। साथ ही, एक प्रमाणित फॉर्म अपनाकर अनावश्यक दस्तावेज़ों और स्टैम्प्स को समाप्त करते हुए “लेस पेपर-मोर फैसिलिटीज़” के लक्ष्य को साकार किया जाए।

राज्य के सभी जनसेवा केंद्रों (JSK) को आधुनिक बनाने, सेवाओं के लिए प्रतीक्षा समय घटाने, और प्रत्येक केंद्र पर मार्गदर्शन डेस्क स्थापित करने जैसी सिफारिशें भी GARC द्वारा की गई हैं, ताकि सरकार का सिटिजन फर्स्ट दृष्टिकोण और अधिक प्रभावी बने।

रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज कम्प्यूटर ऑन्त्रप्रेन्योर्स (VCEs) की भूमिका को मजबूत किया जाए और शहरी क्षेत्रों में पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के माध्यम से ज़ोन-वाइज़ सेवा वितरण को और तेज बनाया जाए।

आयोग ने राइट टू सिटिजन पब्लिक सर्विस एक्ट के अंतर्गत नागरिक चार्टर के नियमित ऑडिट और अपडेट के लिए एक संरचित प्रक्रिया की सिफारिश की है। साथ ही, जनसेवा केंद्रों में अतिरिक्त स्टाफ पदों की नियुक्ति, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सेवा समय की स्पष्टता जैसी सिफारिशें भी शामिल की गई हैं, ताकि नागरिकों को “ईज़ ऑफ गवर्नेंस” का वास्तविक अनुभव मिल सके।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया ने कहा कि यह रिपोर्ट केवल तकनीकी सिफारिशों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुशासन की एक नई संस्कृति का प्रतीक है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के ‘नागरिक देवो भव’ के विचार को केंद्र में रखते हुए नागरिकों को शासन की धुरी बनाया गया है।

यह पहल गुजरात को डिजिटल गुड गवर्नेंस के एक नए युग में प्रवेश कराने के साथ-साथ, “सरकार नागरिकों के द्वार पर” के मंत्र को साकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नागरिक सेवाओं में एक परिवर्तनकारी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को GARC की यह पाँचवीं रिपोर्ट सौंपे जाने के अवसर पर मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़, प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री हरीत शुक्ला, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा GARC के अधिकारी उपस्थित थे।

GARC की पांचवीं रिपोर्ट की सिफारिशें GARC की वेबसाइट https://garcguj.in/resources पर उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में गांधीनगर में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड (एपीएम टर्मिनल्स) द्वारा 17 हजार करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के लिए एमओयू

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए ‘समुद्र से समृद्धि’ के विजन को साकार करने के लिए गुजरात की एक और पहल
- आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास तथा पीपावाव बंदरगाह के क्षमता विस्तार से गुजरात में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को नई दिशा मिलेगी
- एमओयू के परिणामस्वरूप पीपावाव पोर्ट के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम से भारत के ‘मैरीटाइम गेटवे’ के रूप में गुजरात की पहचान अधिक सुदृढ़ होगी
- इस प्रोजेक्ट से भविष्य में रोजगार के प्रत्यक्ष व परोक्ष सहित कुल लगभग 25 हजार अवसर सृजित होंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए ‘समुद्र से समृद्धि’ के विजन को गुजरात में पोर्ट्स सेक्टर के आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से साकार करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस उद्देश्य से बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा ए. पी. मोलर (एपीएम)-मार्स्क बोर्ड के अध्यक्ष श्री रॉबर्ट मर्स्क उग्गला की प्रेरक उपस्थिति में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) तथा गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड (एपीएम टर्मिनल्स) द्वारा 17 हजार करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का एमओयू हुआ।

इस एमओयू का उद्देश्य पीपावाव बंदरगाह की क्षमता के विस्तार से राज्य में अत्याधुनिक विकास द्वारा गुजरात के समुद्री क्षेत्र को और सुदृढ़ करना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस एमओयू की सराहना करते हुए कहा कि पीपावाव पोर्ट्स के विस्तार के फलस्वरूप गुजरात की भारत के ‘मैरीटाइम गेटवे’ के रूप में स्थापित हुई

पहचान और सुदृढ़ होगी।

इतना ही नहीं; यह एमओयू गुजरात में पोर्ट्स नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाकर राज्य के उद्योगों, निर्यातकों एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सशक्त बनाएगा। इस एमओयू से विकास तथा आयात के समय व खर्च; दोनों में कमी आएगी, बंदरगाह के आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों, वेयरहाउसिंग तथा सप्लाई चेन की सुविधाएँ विकसित होंगी और राज्य की आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि भी होगी।

इस प्रोजेक्ट से भविष्य में रोजगार के प्रत्यक्ष व परोक्ष सहित कुल लगभग 25 हजार नए अवसर सृजित होंगे। रोजगार के ये अवसर स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे और ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगे।

इस समझौता ज्ञापन द्वारा पीपावाव बंदरगाह की वर्तमान कंटेनर, बल्क, लिक्विड तथा रो-रो कारगो वहन करने की क्षमता में वृद्धि होने से बंदरगाह का कामकाज अधिक प्रभावशाली एवं तेज बनेगा। इस निवेश के अंतर्गत हैंडलिंग सुविधाओं, आधुनिक कंटेनर टर्मिनल्स, डिजिटल ऑपरेशन सिस्टम्स तथा पर्यावरणोन्मुखी इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।

यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि इस संभावित विस्तार के बाद पीपावाव बंदरगाह गुजरात के समुद्री क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए ‘मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047’ के अनुरूप गुजरात के नॉन-मेजर पोर्ट्स की क्षमता वर्ष 2047 तक 3000 एमएमटीपीए करने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। एपीएम टर्मिनल्स - एशिया तथा मध्य एशिया के चीफ एग्जीक्यूटिव (सीई) श्री जॉन गोल्डनर ने कहा कि यह निवेश योजना केवल पीपावाव पोर्ट के विस्तार के लिए ही नहीं है; बल्कि इससे गुजरात, भारत एवं वैश्विक व्यापार के लिए नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य पीपावाव को विश्व स्तरीय कार्यक्षमता तथा ग्रीन ग्रोथ का मॉडल बनाने के साथ स्थानीय समुदाय के लिए स्थायी समृद्धि का निर्माण करना एवं समुद्री व्यापार में भारत का नेतृत्व अधिक सुदृढ़ करना है।

इस एमओयू हस्ताक्षर अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं जीएमबी के अध्यक्ष श्री एस. एस. राठौड़, बंदरगाह एवं परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री आर. सी. मीणा, जीएमबी की कार्यकारी उपाध्यक्ष सुश्री रेम्या मोहन तथा जीएमबी के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

मार्स्क तथा एपीएम टर्मिनल्स की ओर से ग्रुप चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर रेने पेडरसन, गुजरात पीपावाव पोर्ट के प्रबंध निदेशक श्री गिरीश अग्रवाल तथा भारत, बांगलादेश एवं श्रीलंका क्षेत्र में मार्स्क के लिए लोक नीति एवं नियमनकारी मामलों के प्रमुख श्री विवेक शर्मा भी सहभागी हुए।

प्रियंका गांधी बोलीं – केरल में नहीं होने देंगे मतदाता सूची में धांधली, कांग्रेस करेगी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध — कहा, बिहार जैसा खेल अब दूसरे राज्यों में नहीं दोहराया जाएगा

(जीएनएस)। तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस ने केरल में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस इस प्रक्रिया का हर स्तर पर विरोध करेगी, क्योंकि यह लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह बिहार में एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में धांधली और राजनीतिक हेरफेर किया गया, अब वही षड्यंत्र दक्षिण भारत के राज्यों में रचा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, “बिहार में हमने देखा कि किस तरह लाखों वैध मतदाताओं के नाम सूची से गायब कर दिए गए, और एक खास राजनीतिक दल के हित में मतदाता संतुलन बदलने की कोशिश की गई। अब चुनाव आयोग वही प्रक्रिया केरल और अन्य राज्यों में लागू करना चाहता है। कांग्रेस इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।” उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची की समीक्षा के नाम पर चल रही यह कवायद असल में मताधिकार छीनने और विपक्षी मतों को कमजोर करने का तरीका है। कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल

उठाते हुए कहा कि आयोग को राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन अब वह सत्ता के दबाव में काम करता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबसे पवित्र चीज नागरिक का वोट है, और अगर उसी में छेड़छाड़ शुरू हो जाए, तो यह सीधे-सीधे संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। प्रियंका ने कहा कि केरल में कांग्रेस और यूडीएफ के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे और किसी भी तरह की धांधली पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका गांधी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि “वहां हजारों लोगों को मतदान केंद्रों से वंचित कर दिया गया। कई जगह एसआईआर के बहाने लोगों के नाम गायब कर दिए गए और डुप्लिकेट नामों को जोड़ा गया। यह सिर्फ प्रशासनिक भूल नहीं बल्कि सोची-समझी रणनीति थी।” उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग ने केरल में भी ऐसा कदम उठाया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि देश की हर लोकतांत्रिक पार्टी को इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का सवाल है। उन्होंने यह भी कहा कि “लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है, जब हर नागरिक को यह भरोसा हो कि उसका वोट निष्पक्ष तरीके से गिना जाएगा। अगर इस भरोसे में सेंध लगाई गई, तो यह देश के भविष्य के साथ विश्वासघात होगा।” कांग्रेस के प्रदेश नेताओं ने भी प्रियंका गांधी के बयान का समर्थन किया है। केरल कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरन ने कहा कि राज्य में यदि एसआईआर प्रक्रिया लागू की जाती है, तो कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी मतदाता सूचियों की पारदर्शिता की मांग करेगी और यदि किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए बदलाव किए गए, तो उसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। इस बीच, चुनाव आयोग ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ मतदाता सूची को अद्यतन रखने के लिए है और इसका किसी राजनीतिक दल या एजेंडे से कोई लेना-देना नहीं है।

सोना वायदा में 1497 रुपये और चांदी वायदा में 2460 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा में 16 रुपये का सुधार

कमोडिटी वायदाओं में 34161.49 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 406429.96 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 28296.16 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 28500 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में 440604.16 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 34161.49 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 406429.96 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। इंडेक्स वायदा में 9.91 करोड़ रुपये और इंडेक्स ऑप्शंस में 2.81 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का नवंबर वायदा 28500 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2652.1 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 28296.16 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 119647 रुपये के भाव पर खूलकर, 121557 रुपये के दिन के उच्च और 119351 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 119646 रुपये के पिछले बंद के सामने 1497 रुपये या 1.25 फीसदी की मजबूती के साथ 121143 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी नवंबर वायदा 1262 रुपये या 1.31 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 97754 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल नवंबर वायदा 156 रुपये या 1.29 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 12230 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी दिसंबर वायदा 119700 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 121575 रुपये और नीचे में 119369 रुपये पर पहुंचकर, 1470 रुपये या 1.23 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 121128 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन अक्टूबर वायदा प्रति 10 ग्राम 120200 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 121600 रुपये और नीचे में 119767 रुपये पर पहुंचकर, 121219 रुपये के पिछले बंद के सामने 119 रुपये या 0.1 फीसदी औंधकर 121100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी दिसंबर वायदा 144761 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 147768 रुपये और नीचे में 144618 रुपये पर पहुंचकर, 144342 रुपये के पिछले बंद के सामने 2460 रुपये या 1.7 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 146802 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी नवंबर वायदा 2418 रुपये या 1.65 फीसदी की तेजी के संग 148795 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो नवंबर वायदा 2470 रुपये या 1.69 फीसदी की तेजी के संग 148846 रुपये प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 2445.03 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा नवंबर वायदा 7.7 रुपये या 0.76 फीसदी की तेजी के संग 1016.8 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता नवंबर वायदा 1.65 रुपये या 0.55 फीसदी बढ़कर 302 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम नवंबर वायदा 1.1 रुपये या 0.41 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 272.15 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा नवंबर वायदा 5 पैसे या 0.03 फीसदी की नरमी के साथ 183.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3260.30 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल नवंबर वायदा 5311 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5354 रुपये और नीचे में 5285 रुपये पर पहुंचकर, 16 रुपये या 0.3 फीसदी बढ़कर 5346 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी नवंबर वायदा 15 रुपये या 0.28 फीसदी की मजबूती के साथ 5346 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस नवंबर वायदा 341 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 341.9 रुपये और नीचे में 333.5 रुपये पर पहुंचकर, 341.6 रुपये के पिछले बंद के सामने 6.3 रुपये या 1.84 फीसदी औंधकर 335.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

वडोदरा मंडल पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक ने पारदर्शिता के साथ सिस्टम इंप्रूवमेंट पर दिया बल

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में दिनांक 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक “ सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी” थीम पर ‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह’ मनाया जा रहा है। इस संबंध में आज पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल कार्यालय के कॉंफ्रेंस रूम में सतर्कता जागरूकता पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसे पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन ने सम्बोधित किया। उन्होंने मंडल के अधिकारियों से भारतीय रेल में सेवाओं एवं कार्य में पारदर्शिता के साथ सिस्टम इंप्रूवमेंट पर जोर दिया।

वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन वरिष्ठ सतर्कता अधिकारियों के साथ आज वडोदरा मंडल में वडोदरा पधारे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर मंडल कार्यालय में पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन के मार्गदर्शन में तथा मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके की अध्यक्षता में सतर्कता जागरूकता मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में श्री जैन ने विभिन्न विभागों में प्रणाली सुधार के क्रियान्वयन की स्थिति पर मंडल के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की।

इस बैठक से पूर्व पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री जैन ने लोको शेड का निरीक्षण भी किया और शेड के अधिकारियों, सुपरवाइजरों एवं कर्मचारियों के साथ सतर्कता विषय पर काउंसलिंग की।

सतर्कता के बारे में जागरूकता के क्रम में प्रातः मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, प्रतापनगर से साइकिल रैली का आयोजन भी किया गया। इस रैली में पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन एवं वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया।

भारतीय नौसेना को मिलेगा ‘स्पेस शील्ड’, इसरो करेगा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत अब समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष तकनीक के संगम से एक नया इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) दो नवंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय नौसेना के लिए एक विशेष सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सैटेलाइट का नाम सीएमएस-03 (जीसैट-7आर) रखा गया है, जो नौसेना को वास्तविक समय में संचार, निगरानी और रणनीतिक नियंत्रण जैसी क्षमताओं से सुसज्जित करेगा। यह सैटेलाइट भारत की ‘स्पेस शील्ड’ के रूप में काम करेगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी और रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इसरो के अनुसार, सीएमएस-03 अब तक का देश का सबसे भारी संचार उपग्रह है, जिसका वजन करीब 4,400 किलोग्राम है। इसे भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में स्थापित किया जाएगा। इसके प्रक्षेपण के लिए इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट एलवीएम3 (LVM3-M5) इस्तेमाल होगा। यही रॉकेट पहले भारत के गौरव मिशन ‘चंद्रयान-3’ को सफलता पूर्वक चंद्रमा तक पहुंचा चुका है। यह एलवीएम3 की पांचवीं उड़ान होगी और इसरो ने बताया है कि लॉन्च व्हीकल तथा सैटेलाइट का एकीकरण पूरा हो चुका है। 26 अक्टूबर को इसे लॉन्च पैड पर स्थापित कर अंतिम परीक्षणों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएमएस-03 सैटेलाइट भारतीय भूभाग और विशाल समुद्री क्षेत्रों दोनों को कवर करेगा। इसमें मल्टी-बैंड कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है, जो समुद्र में गश्त कर रहे युद्धपोतों, पनडुब्बियों, और तटीय ठिकानों के बीच निरंतर संपर्क बनाए रखेगा। यह सैटेलाइट समुद्री सीमाओं में मौजूद हर गतिविधि की निगरानी में मदद करेगा, जिससे भारतीय नौसेना को रियल टाइम स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक यह भारत को समुद्री संचार में स्वदेशी आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा, जिससे विदेशी सैटेलाइट पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस उपग्रह के जरिए नौसेना को न केवल सामरिक संचार में बढ़त मिलेगी, बल्कि यह हवाई रक्षा, टोही मिशनों, कमांड-कंट्रोल ऑपरेशंस और समुद्री निगरानी अभियानों में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। इससे आपात स्थितियों में सूचना के आदान-प्रदान में तेजी आएगी और नौसेना की प्रतिक्रिया क्षमता कई गुना अधिक हो जाएगी।

31 अक्टूबर से वेरावल-गांधीग्राम के बीच चलेगी दैनिक स्पेशल ट्रेन,टिकटों की बुकिंग 30 अक्टूबर (गुरूवार) से होगी शुरू

(जीएनएस)। जूनागढ़ में लगने वाले परिक्रमा मेले के दरमियान होने वाली यात्रियों की भीड़ एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष किराये पर वेरावल-गांधीग्राम के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इन ट्रेनों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन नंबर 09226 वेरावल-गांधीग्राम दैनिक स्पेशल ट्रेन वेरावल से रात्रि 21.20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 8.00 बजे गांधीग्राम पहुँचेगी। यह ट्रेन 31.10.2025 से 10.11.2025 तक प्रतिदिन चलेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन नंबर 09225 गांधीग्राम-वेरावल दैनिक स्पेशल ट्रेन गांधीग्राम से

रात्रि 22.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 08.45 बजे वेरावल पहुंचेगी। यह ट्रेन 01.11.2025 से 11.11.2025 तक प्रतिदिन चलेगी।

यह ट्रेन मार्ग में मालीया हाटीना, केशोद, जूनागढ़, जेतलसर, विरपुर, गोंडल, भक्तिनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर जंक्शन, वढवाण सिटी, बोटाद, धंधुका, धोलका, बावला और सरखेज स्टेशनों पर रूकेगी।

इस ट्रेन में थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोच होंगे। इस ट्रेन के जनरल कोच और एसएलआरडी कोच अनारक्षित होंगे, जिनके लिए टिकट यूटीएस काउंटर से मिलेंगे तथा इन कोचों में सुपरफास्ट मेल/एक्सप्रेस का किराया लगेगा।

ट्रेन नंबर 09226 एवं 09225 के लिए टिकटों की बुकिंग 30.10.2025 (गुरूवार) से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। इन ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर मंडल की 4 जोड़ी ट्रेनों में लगाए जाएंगे दो-दो अतिरिक्त जनरल कोच

(जीएनएस)। यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल की विभिन्न मार्गों की 4 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी रूप से दो-दो अतिरिक्त जनरल सेकंड क्लास (GS) कोच लगाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था 31 अक्टूबर, 2025 से 10 नवम्बर, 2025 तक प्रभावी रहेगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:-

1.ट्रेन नंबर 19119/19120 वेरावल-गांधीनगर कैपिटल-वेरावल दैनिक एक्सप्रेस

2.ट्रेन नंबर 19207/19208 पोरबंदर-राजकोट-पोरबंदर दैनिक एक्सप्रेस

3.ट्रेन नंबर 59557/59460 भावनगर-पोरबंदर-भावनगर दैनिक पैसेन्जर

4.ट्रेन नंबर 59558/59559 भावनगर-वेरावल-भावनगर दैनिक पैसेन्जर

- यह अस्थायी वृद्धि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए की गई है, ताकि सभी यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिल सके।
- भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे सुरक्षित यात्रा करें एवं रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाएँ।